

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
समाज कल्याण, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी, जनपद-नैनीताल।

2. निदेशक,
जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

समाज कल्याण अनुभाग-01.

देहरादून, 15 जनवरी 2009.

विषय : समाज कल्याण विभागान्तर्गत संचालित समस्त आवासीय संस्थाओं में भोजन व्यवस्था निविदा के आधार पर करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपयुक्त विषयक शासनादेश संख्या-1023/XVII(1)-01/2006-01(27)/2006, दिनांक 03 अगस्त 2006, जिसके द्वारा समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित आवासीय संस्थाओं में भोजन आदि का प्रबन्ध कराए जाने हेतु दिशा-निर्देश जारी किए गए थे तथा शासनादेश संख्या-348/XVII(1)-01/2007-01(27)/2006, दिनांक 17 अप्रैल 2007, जिसके द्वारा समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों एवं महिला कल्याण के अन्तर्गत संचालित संस्थाओं हेतु भोजन सारणी का निर्धारण किया गया था, को अतिक्रमित करते हुए सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समाज कल्याण विभागान्तर्गत संचालित विभिन्न आश्रम पद्धति विद्यालयों तथा 25 एवं उससे अधिक संवासियों/संवासिनियों की समस्त आवासीय संस्थाओं में भोजन व्यवस्था निविदा के आधार पर Outsource कराए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. संस्थाओं में भोजन व्यवस्था हेतु निजी फर्मों/संस्थाओं से संलग्न प्रपत्र के अनुसार निविदायें आमंत्रित की जायेगी। इस हेतु कम से कम एक व्यापक परिचालन वाले राष्ट्रीय समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा तथा चयन निविदादाताओं में से प्रतिस्पर्धा के आधार पर किया जायेगा। निविदा हेतु अर्हताएं निम्नानुसार होंगी-

- (1) निविदादाता द्वारा जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक के द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाणपत्र जमा करना होगा।
- (2) निविदादाता, श्रम विभाग में पंजीकृत होना चाहिए।
- (3) निविदादाता के पास निविदा से सम्बन्धित लॉय का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए तथा इस हेतु उसे प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (4) निविदा प्रपत्र के साथ निविदा की अनुमानित लागत की दो प्रतिशत धरोहर धनराशि (Earnest Money), जो कि वापसी योग्य (Refundable) होगी, जमा करनी होगी।
- (5) निविदादाता/फर्म का व्यवसाय (Turnover) विगत तीन वर्षों में निविदा मूल्य का कम से कम तीन गुना होना चाहिए।
- (6) निविदादाता द्वारा आयकर/बिक्रीकर पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

- (7) जिस निविदादाता की निविदा स्वीकार की जाएगी, उसे अनुमानित लागत की पांच प्रतिशत धनराशि कार्यपूर्ति प्रतिभूति (Performance Security) के रूप में जमा करनी होगी। जो कि एकाउन्ट पेई डिमाण्ड ड्राफ्ट, सावधि जमा रसीद (FDR) या बैंक गारन्टी के रूप में सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी के नामे देय होगी।
 - (8) जिस निविदादाता को कार्य करने की स्वीकृति प्रदान की जाएगी उसका उक्त व्यवस्था के सही संचालन का उत्तरदायित्व भी होगा। यदि इस सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो सम्बन्धित विभागाध्यक्ष को उसकी निविदा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
 - (9) न्यूनतम बोली/दर के आधार पर निविदा जमेति द्वारा निविदा स्वीकार की जायेगी। निविदा समिति द्वारा स्वीकृत निविदा के आधार पर सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा निविदादाता के साथ अनुबन्धपत्र निष्पादन कराया जाएगा।
3. उक्तानुसार संस्थाओं में भोजन व्यवस्था हेतु प्राप्त निविदाओं में से श्रेष्ठ निविदा के चयन हेतु निम्नानुसार निविदा समिति का गठन किया जाएगा—
- | | | |
|---|---|-------------|
| (1) सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी | : | अध्यक्ष |
| (2) सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी | : | सदस्य |
| (3) जिन क्षेत्रों में परियोजनाधिकारी, जनजाति कल्याण के पद सृजित हैं, वहां के परियोजनाधिकारी | : | सदस्य |
| (4) सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष | : | सदस्य |
| (5) जनपद में स्थापित राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के प्रधानाचार्य | : | सदस्य |
| (6) सम्बन्धित जनपद के मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी | : | सदस्य |
| (7) सम्बन्धित आहरण-वितरण अधिकारी | : | सदस्य सचिव। |
4. निविदा में शासनादेश संख्या-148/XVII(1)-2/2006-08(25)/2006, दिनांक 15 मार्च 2007 द्वारा निर्धारित भोजन दरों के अन्तर्गत ही व्यय सीमित रखा जाएगा एवं न्यूनतम निविदादाता को अवसर प्रदान किया जाएगा।
5. इस शासनादेश के अनुलग्नक-2 में निर्धारित आहार सारणी (Diet Chart) भी निविदा में दर्शायी जाएगी।
6. संस्था में होने वाले अवकाश अवधि यथा: ग्रीष्म/शीतकालीन अवकाश को भी निविदा में इंगित किया जाएगा।
7. विद्यार्थियों/संवासियों के लिए भोजन/जलपान तैयार करने हेतु संस्था द्वारा उपलब्ध कराए गए स्थान तथा सुविधाओं (यथा: गैस चूल्हा, बर्तन इत्यादि) का निविदादाता से कोई अतिरिक्त प्रभार नहीं लिया जाएगा, किन्तु गैस भराने (Refill) आदि का दायित्व निविदादाता का होगा।
8. खाद्य सामग्री की गुणवत्ता की निगरानी हेतु सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष की अध्यक्षता में विद्यार्थियों/संवासियों की पांच सदस्यीय एक समिति बनाई जाएगी। विद्यार्थियों/संवासियों को समिति में प्रतिमाह बदल दिया जाएगा अर्थात् समिति में प्रतिमाह नए विद्यार्थी/संवासी रहेंगे।

9. निविदा में संस्थाओं के विवरण के साथ-साथ विद्यार्थियों/संवासियों की कुल क्षमता एवं निवासरत संख्या आदि स्पष्ट इंगित की जाए तथा प्रति विद्यार्थी/संवासी विभागीय मानक मूल्यों का भी उल्लेख कर दिया जाए।
10. निविदा में यह भी अंकित किया जाएगा कि परिस्थितिवश विद्यार्थी/संवासी संख्या में मामूली परिवर्तन संभावित है।
11. निविदा द्वारा उक्त व्यवस्थाएं किए जाने हेतु पृथक से कोई अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था नहीं की जाएगी। अपितु उक्त व्यवस्थाएं पूर्व से प्राविधानित धनराशि के अन्तर्गत ही की जाएगी।
12. उक्त संस्थाओं में इन कार्यों हेतु जो कार्मिक पूर्व से कार्यरत हैं, संस्थाध्यक्ष द्वारा उनसे यथावश्यकता अन्य कार्य लिए जा सकते हैं।
13. निविदा की अवधि एक वर्ष रखी जाएगी तथा निविदा हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टोरमेंट) नियमावली, 2008 एवं अन्य वित्तीय नियमों का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
14. कृपया उक्तानुसार आदेशों का अनुपालन अपने एवं अपने अधीनस्थ स्तर पर कराना सुनिश्चित करें। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए निविदा प्रक्रिया तत्काल प्रारम्भ करते हुए दिनांक 31 मार्च 2009 तक पूर्ण कर ली जाए।

संलग्नक : निविदा प्रपत्र एवं आहार सारणी।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या : 72 (1) XVII-1/2009-01(27)/2006, तद्दिनांक :

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव-माननीय समाज कल्याण मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव-मुख्य सचिव/अपर मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
4. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष/संस्थाध्यक्ष, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड देहरादून।
9. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी/परियोजनाधिकारी, जनजाति कल्याण, /मुख्य, वरिष्ठ, कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. समस्त प्रधानाचार्य, राजीव गांधी नवोदय विद्यालय, उत्तराखण्ड।
11. वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-03, उत्तराखण्ड शासन।
12. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. आदेश पंजीका।

आज्ञा से
(धीरेन्द्र सिंह दत्तल)
उप सचिव।